PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Fri, 26 May 2017, Page 13
Width: 43.35 cms, Height: 25.30 cms, a3r, Ref: 35.2017-05-26.87

डिजिटल इंडिया पर अटल रही सरकार

आधार आधारित भुगतान से बदलेगी देश की तस्वीर, गरीबों को मिलेगा हक, पारदर्शिता से भ्रष्टाचार का इलाज

नितिन प्रधान ● नई दिल्ली

सरकार दावा कर रही है कि अगले पांच-छह साल में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था छह लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी। अगले तीन साल में अधिकांश सरकारी सेवाएं मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगी। गांवों में न केवल किसानों को मिलने वाली समस्त जानकारी उनके मोबाइल पर होगी बल्कि वे ई-मंडियों के जरिए पैदावार की अच्छी कीमत भी पा सकेंगे। सरकार अपने कामकाज को डिजिटल बनाते हुए लोगों को दिये जाने वाले तमाम लाभ ई-गवर्नेंस के जरिए उपलब्ध कराएगी और भारत दुनिया भर में डिजिटल सेवाओं के मामले में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होगा।

साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र में सरकार बनी थी, तब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। इसका मकसद न केवल देश में ई-गवर्नेंस की स्थिति लाना था बल्कि समूचे देश में ब्रॉडबैंड का जाल बिछा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा से लैस करना था।

इसके जरिए सरकार का इरादा गांवों तक सेवाओं के डिजिटल स्वरूप और इंटरनेट के फायदों का प्रसार करना था, लेकिन पिछले साल नवंबर में पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट पर प्रतिबंध के बाद डिजिटल इंडिया अभियान की तस्वीर ही बदल गई। यह पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पर केंद्रित हो गया और सरकार का फोकस भी इस पर आ गया। हालांकि ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को जनता तक पहुंचाने और आधार के जरिए लोगों को मिलने वाले सरकारी लाभ को इससे जोड़ने का काम भी साथ-साथ चलता रहा। बीते एक साल में डिजिटल इंडिया की दिशा में सरकार के कदम तेजी से बढ़े हैं और नोटबंदी के बाद इसकी रफ्तार दोगुनी हो गई है।

सरकार डिजिटल इंडिया अभियान को गवर्नेंस को ई-गवर्नेंस में तब्दील करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक सशक्त समाज के निर्माण का सबसे प्रभावी जरिया मानती है। इसकी नींव जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए रखी गई। जनधन यानी उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना जिनके पास अब तक बैंक खाता नहीं था। आधार के दायरे में भी जरूरतमंद लोगों को लाकर उन्हें सभी सरकारी लाभों को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। इस दिशा में सरकार मोबाइल को बड़ा माध्यम मान रही है। सरकार ने बीते दो साल में देश को डिजिटल स्वरूप में बदलने के लिए इन्हीं तीन माध्यमों पर फोकस किया है। इनके जरिए सरकार जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने में काफी हद तक सफल रही है। अब तक सरकार इस नीति पर चलकर 50 हजार करोड़ रुपये तक की बचत कर चुकी है। अनुमान है कि लोगों को मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के दायरे में आने के बाद यह बचत एक लाख करोड़ रुपये तक की हो सकती है। चूंकि अभी तक सब्सिडी का लाभ सीधे जरूरतमंद तक नहीं पहुंचता था, इसलिए फर्जी आंकड़ों के जरिए सब्सिडी की चोरी होती थी। चाहे वह पीडीएस में हो, खाद सब्सिडी में हो या फिर छात्रों और लोगों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों और पेंशन में। इसी तरह सरकार में होने वाली खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर भी सरकार 1.3 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में सफल रही है। अभी करीब 135 स्कीमों के तहत लाभ का वितरण डीबीटी के तहत किया जा रहा है।

सरकार डिजिटल इंडिया के अपने अभियान को सफल बनाने के लिए देश में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को बड़ा आधार मान रही है। इसमें भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे सरकार उत्साहित है। इस साल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 35 करोड़ को पार कर जाने की उम्मीद है। अगले पांच साल में यह 81 करोड़ हो सकती है। खुद इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद मानते हैं कि मोबाइल फोन डिजिटल इंडिया की सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि भुगतान से लेकर सरकारी सेवाओं को मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध कैराने पर सरकार जोर दे रही है।

नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट की दिशा में तेज काम हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक खास एप भीम विकसित किया। इसके अतिरिक्त सरकार ने डिजिटल पेमेंट की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। भीम को आधार के साथ जोड़कर सरकार ने जनता को बिना कार्ड, वालेट आदि के भुगतान करने का नया विकल्प देने का फैसला किया है। हालांकि अभी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन सरकार का दावा है कि जल्द ही इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया जाएगा।

सरकारी सेवाओं के डिजिटल स्वरूप को भी अगले चरण में ले जाने को सरकार तैयार है। प्रसाद बताते हैं कि सरकार का इरादा अगले तीन साल में 1200 सेवाओं को मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध कराने का है। इस साल की दूसरी छमाही तक 60 सेवाओं से सरकार शुरूआत कर देगी। उमंग नाम का यह एप कई क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान भी इसी के माध्यम से किया जा सकेगा।

चुनौतियां

आधार सहित सरकार के डाटा सिस्टम को सुरक्षित बनाना

मोबाइल नेटवर्क में अपेक्षित सुधार

ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड पहुंचाने की रफ्तार बढ़ाना

भारतनेट: ग्रामीण भारत को जोड़ने का प्रयास

17,000 ग्राम पंचायतों में शुरू हो गया है काम

10 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लक्ष्य

- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों के इस्तेमाल के लिए वाई-फाई हॉट स्पॉट लगाए जा रहे हैं। 2017-18 के पहले चरण में 30,000 हॉट स्पॉट लगाने का लक्ष्य

दूसरे चरण के लिए राज्यों व निजी सेक्टर के साथ पार्टनरशिप

70,500 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ीं

ऑप्टिकल फाइबर केबल (किमी)

जून, 2014	2012	दिसंबर, 2018
358	1.8 लाख	10 लाख

लक्ष्य 2017-18

उपलब्धियां

- 11 लाख प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) चालू हुए
- भारत क्यूआर कोड लांच, ताकि हो बिना स्वाइप मशीन के भुगतान

8 गुना

2016-17	2017-18
300 (करोड़ में)	2,500

10 लाख पीओएस 31 मार्च 17 तक

20 लाख प्वाइंट ऑफ सेल सितंबर तक

सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा

हाल के दिनों में आधार का डाटा लीक होने से लेकर डेबिट कार्ड की जानकारी लीक होने के मामले सामने आए हैं। डिजिटल पेमेंट की स्थिति में यह खतरा और तेजी से बढ़ेगा। सरकार ने इस दिशा में अपने तंत्र को मजबूत करने का भरोसा दिया है और वित्तीय क्षेत्र से लेकर पावर, टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों के लिए अलग से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक नेशनल साइबर को-ऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जा रहा है जो इस साल शुरू हो जाएगा।

मोबाइल नेटवर्क में भी सुधार जरूरी

डिजिटल इंडिया की अधिकांश स्कीमों सफलता का आधार मोबाइल फोन पर टिका है। आज की तारीख में देश में मोबाइल सेवाओं की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। मोबाइल नेटवर्क का न तो विस्तार हो पा रहा है और न ही उनकी सेवाओं में सुधार हुआ है। अगर सरकार डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क में सुधार की रफ्तार नहीं बढ़ाएगी तो डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पाना चुनौतीपूर्ण होगा।